शशिकला देवी

बनाम

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 11488/2014)

17 दिसंबर, 2014

[टी. एस. ठाकुर और आर. भानुमती, न्यायाधिपतिगण]

सेवा कानूनः

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - बैंक कर्मचारी - 34 साल की सेवा के बाद चिकित्सा आधार पर सेवा से इस्तीफा दे दिया - इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया जिसके परिणामस्वरूप उसके द्वारा प्रदान की गई पूरी सेवा जब्त हो गई और वह किसी भी पेंशन लाभ का दावा करने से वंचित हो गया - क्या पत्र, संक्षेप में था , समय से पहले सेवानिवृत्ति की मांग करने वाला पत्र या त्याग पत्र - माना गया - अभिनिर्धारित किया गया : कर्मचारी सेवा विनियमों के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य था, वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का भी हकदार था, इस्तीफा देने का नहीं - कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने के लिए नियोक्ता-बैंक को निर्देश - सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995- विनियम 29(2)।

पेंशन - चूंकि पेंशन कोई इनाम नहीं है, बल्कि एक अधिकार है जो लंबी सेवा से प्राप्त होता है, इसलिए न्यायालय यह मानने में देर करेगा कि कर्मचारी बिना किसी ठोस कारण के इसे माफ करना या छोड़ना चाहता था।

छूट - कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार - कब स्वीकार्य - अभिनिर्धारित किया गया : कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार की छूट के लिए, यह आवश्यक है कि वह स्पष्ट और सुस्पष्ट, सचेत और परिणामों की पूरी जानकारी के साथ हो।

क़ानून की व्याख्या - किसी क़ानून की व्याख्या करते समय, अदालत को विधायी इरादे को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी व्याख्या से बचना चाहिए जो इसके लाभकारी प्रावधानों को प्रतिबंधित, संकीर्ण या पराजित करती हो - पेंशन योजना या पेंशन विनियमों के लाभकारी प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए ताकि लाभार्थियों को देय लाभों से वंचित करने के बजाय उसके अंतर्निहित उद्देश्य को बढ़ावा देना - सेवा कानून - पेंशन।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए,

अभिनिर्धारित किया : 1.1. एक कर्मचारी जिसने बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, वह बैंक की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का हकदार है, बशर्ते वह उस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन महीने का नोटिस दे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के विनियमन 29(2) के प्रावधान के अनुसार, यदि नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्ति की अनुमति देने से इनकार नहीं करता है, तो उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से सेवानिवृत्ति प्रभावी हो जाती है। विनियम 29 (3) (ए) के संदर्भ में, नियुक्ति प्राधिकारी उपयुक्त मामलों में तीन महीने के नोटिस की अवधि को इस शर्त के अधीन कम करने में सक्षम है कि कर्मचारी नोटिस समाप्ति की अवधि से पहले अपनी पेंशन के लिए आवेदन नहीं करेगा। [पैरा 6][880-जी-एच; 881-ए-बी] टी

1.2. वर्तमान मामले में, मृत कर्मचारी ने प्रतिवादी-बैंक में लगभग 34 वर्ष की सेवा प्रदान की थी। इसलिए, वह उस पर लागू विनियमों के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के

लिए योग्य था। विनियम 29 को पढ़ने से यह भी स्पष्ट है कि कि मृत कर्मचारी विनियम 29 के संदर्भ में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का हकदार था क्योंकि उसने 8 अक्टूबर, 2007 तक बीस वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली थी। 8 अक्टूबर, 2007 को मृतक-कर्मचारी विनियम 29 के संदर्भ में या तो सेवा से इस्तीफा देने या समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने का हकदार था। [पैरा 7] [881-सी-ई]

1.3. दिया गया संचार त्यागपत्र का सरल पत्र है या नहीं या इसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध माना जा सकता है या नहीं, यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और लागू नियमों के प्रावधानों पर निर्भर करेगा। यानी, तब भी जब इस न्यायालय ने हमेशा "इस्तीफा" और "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखा है। [पैरा 7][881-ई-जी]

यूको बैंक और अन्य बनाम सांवर मल (2004) 4 एससीसी 412: 2004 (2) एससीआर 1125; भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बनाम सीईसीआईएल डेनिस सोलोमन और अन्य (2004) 9 एससीसी 461: 2003 (6) पूरक एससीआर 465 - संदर्भित किया गया ।

1.4. वर्तमान मामले में, कर्मचारी ने अपने विरुद्ध प्रस्तावित किसी अनुशासनात्मक या अन्य कार्रवाई या स्थानांतरण या पोस्टिंग के किसी आदेश से, जिससे वह नाखुश था या इसलिए नहीं कि कोई कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसके कारण उसे नौकरी छोड़ने का विकल्प चुना गया था। यदि वह सेवा में बना रहता तो नागरिक परिणाम, लेकिन उन बीमारियों के कारण सेवा में बने रहने में उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण, जिनसे वह त्रस्त था। यह इस बात से स्पष्ट है कि न केवल पत्र में, बल्कि उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में भी कर्मचारी ने समय से पहले सेवा छोड़ने के कारणों पर काफी जोर दिया है। इस प्रकार, 8 अक्टूबर, 2007 को लिखे अपने पत्र में कर्मचारी

का इरादा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का था, न कि अपने रोजगार से इस्तीफा देने का। [पैरा 12 और 14] [886-ई-एच; 887-ए;888-सी]

2.1. पेंशन न तो कोई इनाम है और न ही अनुग्रह का विषय है बल्कि यह कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवाओं का भुगतान है। यदि पेंशन कोई इनाम नहीं है, बल्कि एक अधिकार है जो कर्मचारी को उसके द्वारा किए गए कई वर्षों के ईमानदार और अच्छे काम के कारण प्राप्त होता है, तो न्यायालय यह मानने में धीमा होगा कि कर्मचारी बिना किसी ठोस सबूत के ऐसे मूल्यवान अधिकार को माफ करने या त्यागने का इरादा रखता है। किसी भी दर पर, यह सुझाव देने के लिए कुछ बाध्यकारी परिस्थिति होनी चाहिए कि कर्मचारी ने जानबूझकर उस अधिकार और लाभ को छोड़ दिया है, जिसे उसने इतनी मेहनत से हासिल किया था। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री ऐसे किसी भी सचेत समर्पण परित्याग या पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभ के अधिकार की छूट का सुझाव देती है, लेकिन रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि कर्मचारी के पास उस लाभ के अलावा आय या जीविका का कोई स्रोत नहीं था जो उसने कई वर्षों की सेवा से अर्जित किया था। यह विचाराधीन पत्र को पढ़ने से स्पष्ट होता है, जिसमें कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति लाभों को जल्द से जल्द जारी करने की मांग करता है ताकि वह आवश्यक चिकित्सा उपचार से गुजर सके। पत्र में इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि अपने भरण-पोषण के लिए कर्मचारी पूरी तरह से ऐसे लाभों पर निर्भर है। [पैरा 7 और 14][882-डी; 888-ई-एच; 889-ए-बी]

डी.एस. नाकारा और अन्य बनाम भारत संघ (1983) 1 एससीसी 305 1983 (2) एससीआर 165; अध्यक्ष रेलवे बोर्ड और अन्य बनाम सी.आर. रंगधमैय्या और अन्य (1997) 6 एससीसी 623: 1997 (3) पूरक एससीआर 63; सुधीर चंद्र सरकार बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और अन्य (1984) 3 एससीसी 369: 1984 (3) एससीआर 325 - भरोसा व्यक्त किया

2.2. कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति लाभों के संदर्भ में जो उसका अधिकार था उसे छोड़ने के इरादे के बारे में बताना मुश्किल है, जब इस तरह के लाभ न केवल उसके जीवित रहने के लिए बल्कि उसके चिकित्सा उपचार के लिए भी एकमात्र स्रोत थे, जिसकी उसे तत्काल आवश्यकता थी। किसी कर्मचारी द्वारा अर्जित कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार की छूट के लिए, यह आवश्यक है कि वह स्पष्ट और स्पष्ट, सचेत और परिणामों की पूरी जानकारी के साथ हो। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से ऐसा कोई इरादा नहीं लगाया जा सकता है। कर्मचारी के बाद के पत्रों और संचार को बाद में किया गया विचार नहीं कहा जा सकता। 8 अक्टूबर, 2007 के पत्र को समय की दृष्टि से निकट होना, कर्मचारी के इरादों को स्पष्ट करने वाले बाद के संचार का एक हिस्सा माना जाना चाहिए, कम से कम कर्मचारी के कृत्य के अंतर्निहित वास्तविक इरादे को निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए। [पैरा 14][889-बी-ई]

3.1. किसी क़ानून की व्याख्या करते समय, न्यायालय को विधायी इरादे को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी व्याख्या से बचना चाहिए जो इसके लाभकारी प्रावधानों को प्रतिबंधित, संकीर्ण या पराजित करती हो। [पैरा 8][883-डी-ई]

एस. अप्पुकुट्टन बनाम थुंडियिल जानकी अम्मा और अन्य (1988) 2 एससीसी 372: 1988 (2) एससीआर 661; वतन मल बनाम कैलाश नाथ (1989) 3 एससीसी 79: 1989 (2) एससीआर 192; कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम आर.के. स्वामी और अन्य (1994) 1 एससीसी 445: 1993 (3) पूरक एससीआर 461; भारत संघ और अन्य बनाम प्रदीप कुमारी और अन्य (1995) 2 एससीसी 736: 1995 (2) एससीआर 703 - भरोसा व्यक्त किया।

3.2 पेंशन योजना या पेंशन विनियमों के लाभकारी प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या की गई है ताकि ऐसे प्रावधानों के तहत लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों से इनकार करने के बजाय इसके अंतर्निहित उद्देश्य को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे मामलों में जहां किसी कर्मचारी के पास पेंशन अनुदान के लिए अर्हक सेवा के अपेक्षित वर्ष हैं, और जहां वह लागू सेवा शर्तों के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांग सकता है, वहां कथित इस्तीफे को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध मानकर पेंशन का लाभ देने की अनुमति दी गई है। [पैरा 15][889-ई-जी]

सुधीर चंद्र सरकार बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और अन्य (1984) 3 एससीसी 369: 1984 (3) एससीआर 325; भारत संघ और अन्य बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल पी.एस. भार्गव (1997) 2 एससीसी 28: 1997 (1) एससीआर 130; शील कुमार जैन बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। (2011) 12 एससीसी 197: 2011 (9) एससीआर 574 - भरोसा व्यक्त किया।

4. प्रतिवादी-बैंक को 8 अक्टूबर, 2007 के पत्र को कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक नोटिस के रूप में मानने और तीन महीने की नोटिस अवधि के लिए कटौती करने का निर्देश दिया जाता है। इस दृष्टिकोण के आधार पर सक्षम प्राधिकारी नोटिस अवधि में कटौती और/या मृत-कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों में से तीन महीने के वेतन की कटौती के सवाल पर विचार कर सकता है, मृतक-कर्मचारी का सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए दावा, जिसके तहत देय है पेंशन सहित प्रासंगिक नियमों को अपीलकर्ता-विधवा के पक्ष में यथासंभव शीघ्रता से संसाधित और जारी किया जाएगा, लेकिन इस आदेश की एक प्रति बैंक को दिए जाने की तारीख से छह महीने के बाद नहीं। यदि बैंक छह महीने के भीतर निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो कर्मचारी और उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा को देय राशि पर 10% प्रति वर्ष की

दर से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। जिस तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त हो रही है. [पैरा 19][893-एफ-एच; 894-ए-बी]

प्रकरण कानून संदर्भ:

| | | |
|---|---|---|
| 2004 (2) एससीआर 1125 | संदर्भित किया गया | पैरा 7 |
| 2003 (6) पूरक एससीआर 465 | संदर्भित किया गया | पैरा |
| 1983 (2) एससीआर 165 | भरोसा व्यक्त किया | पैरा 7 |
| 1997 (3) पूरक एससीआर 63 | भरोसा व्यक्त किया | पैरा 7 |
| 1984 (3) एससीआर 325 | भरोसा व्यक्त किया | पैरा 7 |
| 1988 (2) एससीआर 661 | भरोसा व्यक्त किया | पैरा 8 |
| 1989 (2) एससीआर 192 | भरोसा व्यक्त किया | पैरा 9 |
| 1993 (3) पूरक। एससीआर 461 | भरोसा व्यक्त किया | पैरा 10 |
| 1995 (2) एससीआर 703 | भरोसा व्यक्त किया | पैरा 11 |
| 1984 (3) एससीआर 325 | भरोसा व्यक्त किया | पैरा 16 |
| 1997 (1) एससीआर 130 | भरोसा व्यक्त किया | पैरा 16 |
| 2011 (9) एससीआर 574 | भरोसा व्यक्त किया | पैरा 18 |

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 11488/2014

एलपीए संख्या 1998/2010 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11-11-2011 से।

वाई. राजा गोपाल राव, हितेंद्र नाथ रथ, अधिवक्तागण, अपीलकर्ता के लिए।

शिश वाड, सुश्री जयश्री वाड, मैसर्स जे.एस. वाड एंड कंपनी, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण के लिए ।

न्यायालय का निर्णय टी.एस. ठाकुर न्यायाधिपति, द्वारा दिया गया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में हमारे विचाराधीन संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता के पति स्वर्गीय श्री मौजी राम द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 को भेजा गया पत्र, संक्षेप में चिकित्सा आधार पर समय-पूर्व सेवानिवृत्ति की मांग करने वाला एक पत्र या प्रतिवादी-बैंक की सेवा से त्याग पत्र था। उच्च न्यायालय ने मृत कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका और अपील को खारिज करते हुए घोषित किया कि विचाराधीन पत्र एक त्याग पत्र था जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पूरी सेवा जब्त हो गई और वह किसी भी पेंशन लाभ का दावा करने से वंचित हो गया। उस दृष्टिकोण की सत्यता को उस मृत कर्मचारी की विधवा द्वारा दायर अपील में चुनौती दी जा रही है, जिसका उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निधन हो गया था। चूँकि प्रश्न का उत्तर काफी हद तक उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें ऊपर उल्लिखित पत्र मृतक-कर्मचारी द्वारा लिखा गया था, हम इसे विस्तार में भी पुन: प्रस्तुत कर सकते हैं:

“पटना

दिनांक: 09.10.07

सेवा में,

आंचलिक प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय,

पटना.

जरिये : उचित माध्यम

विषय: बैंक की सेवा से इस्तीफा

आदरणीय महोदय,

पूरे सम्मान के साथ मुझे निम्नलिखित कारण बताने होंगे जिनके कारण मुझे अपनी सेवा से इस्तीफा देना पड़ा।

वर्ष 2002 में मुझ पर गंभीर कार्नियो सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस की समस्या हो गई और मुझे डॉ. पी.एस. रमानी लीलावती अस्पताल, मुंबई के पास भेजा गया, जहां मुझे सर्जिकल उपचार के लिए जाना पड़ा। एक महीने के भीतर ही मुझे प्रोस्टेट की गंभीर समस्या हो गई, जिसके लिए मुझे शीला यूरोलॉजी सेंटर, पटना में डॉ. एस.एस.अंबस्ता से ऑपरेशन कराना पड़ा। लेकिन मैं अपनी पीड़ा से छुटकारा नहीं पा सका और भुगतान पर चक्कर आने लगा। परिणामस्वरूप मैं स्वयं को नियमित कर्तव्य निर्वहन करने में असमर्थ पा रहा हूँ।

इन परिस्थितियों में मुझे कई बार ड्यूटी छूटने पर भी छुट्टी पर रहना पड़ा।

पिछले कुछ समय से प्रोस्टेट की समस्या और अधिक गंभीर हो गई है। फिलहाल मैं पटना में डॉ. एस.एस. अम्बस्ता से इलाज करा रहा हूं। तीव्र सर्वाइकल रोग के साथ प्रोस्टेट का इलाज पटना में डॉ. एस.एस. अम्बास्ता द्वारा किया गया। प्रोस्टेट जटिलता के साथ मिलकर तीव्र सर्वाइकल रोग ने मुझे अपने नियमित काम करने में भी लगभग पूरी तरह से अक्षम बना दिया है।

अपनी प्रस्तुति के समर्थन में मैं लीलावती अस्पताल, मुंबई और यूरोलॉजी सेंटर, पटना में अपने इलाज के मेडिकल नुस्खों की ज़ेरॉक्स प्रतियां और अपने वर्तमान इलाज के लिए डॉक्टर के नुस्खों को संलग्न कर रहा हूं।

उपरोक्त बताई गई परिस्थितियों में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, जिसके कारण मैं बैंक में सेवा देने में असमर्थ हो गया हूं। इसे ध्यान में रखते हुए मैं बैंक की सेवा से अपना इस्तीफा देता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सेवा से मेरा इस्तीफा यथाशीघ्र स्वीकार करने की कृपा करें ताकि मैं अपने टर्मिनल लाभों से अग्रिम उपचार कराने में सक्षम हो सकूं जो कि मेरी आजीविका और चिकित्सा उपचार के लिए एकमात्र बचा हुआ वित्तीय संसाधन है। मैं मेरे उपरोक्त अनुरोध पर आपके दयालु और अनुकूल विचार के लिए मेरे परिवार के सदस्य अत्यधिक आभारी होंगे।

धन्यवाद,

आपका विश्वासी,

(मौजी राम), लिपिक, राजबंशी नगर, पटना।"

(जोर दिया गया)

3. उपरोक्त को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारी ने अपनी चिकित्सा स्थिति के कारण अपनी नौकरी से जुड़े कर्तव्यों से राहत मांगी थी, जिससे वह शारीरिक रूप से अक्षम हो गया था, जिसका उसने पत्र में ही व्यापक संदर्भ दिया है। यह पत्र अपनी प्रार्थना के समर्थन में उस अस्पताल के चिकित्सीय नुस्खों की प्रतियों पर आधारित है और संलग्न है जहां कर्मचारी का इलाज चल रहा था। अपने ख़राब स्वास्थ्य के कारण उत्पन्न असमर्थता के कारण ही कर्मचारी ने बैंक में अपनी सेवा से मुक्त होने के लिए प्रार्थना की थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारी ने अपने टर्मिनल लाभों को जारी करने के लिए प्रार्थना की थी ताकि वह अपनी बीमारी का इलाज करा सके। पत्र में उल्लेख किया गया है कि उसका टर्मिनल लाभ ही उसकी आजीविका और उसके लिए आवश्यक उपचार के लिए एकमात्र वित्तीय सहायता है।

4. बैंक ने कर्मचारी के पत्र को सेवा से त्यागपत्र के रूप में मानते हुए उसे स्पष्ट रूप से कार्यमुक्त कर दिया क्योंकि पत्र में प्रयुक्त अभिव्यक्ति त्यागपत्र थी जिसका स्पष्ट अर्थ था कि कि ऐसे कर्मचारी को देय पुनर्परीक्षण लाभों के संदर्भ में बैंक पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, जिसने अपेक्षित संख्या में वर्षों तक सेवा की है, जिससे वह सेवानिवृत्ति का हकदार बन जाता है।

5. प्रतिवादी-बैंक के कर्मचारियों को पेंशन देना या अस्वीकार करना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 द्वारा विनियमित है। उक्त विनियमन का अध्याय IV अर्हक सेवा से संबंधित है। उस अध्याय में आने वाले विनियमों के विनियम 14 में कहा गया है कि एक कर्मचारी जिसने अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख पर या जिस तारीख को उसे सेवानिवृत्त माना जाता है, उस दिन बैंक में न्यूनतम दस साल की सेवा प्रदान की है, वह पेंशन के लिए पात्र होगा। विनियमन 22 सेवा की जब्ती से संबंधित है और अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि बैंक की सेवा से किसी कर्मचारी का इस्तीफा, बर्खास्तगी, निष्कासन या समाप्ति उसकी पूरी पिछली सेवा को जब्त कर लेगी। विनियमों का अध्याय V पेंशन की श्रेणियों से संबंधित है। जबकि विनियम 28 में सेवानिवृत्ति पेंशन की परिकल्पना की गई है, विनियम 29 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन से संबंधित है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"29. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन:-

(1) 1 नवंबर, 1993 को या उसके बाद, किसी भी समय किसी कर्मचारी ने बीस साल की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन महीने का नोटिस देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है।

बशर्ते कि यह उप-विनियम ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो विदेश में प्रतिनियुक्ति या अध्ययन अवकाश पर है, जब तक कि स्थानांतरित होने या भारत

लौटने के बाद उसने भारत में पद का प्रभार फिर से शुरू नहीं किया हो और कम से कम एक वर्ष अवधि तक सेवा की हो;

बशर्ते कि यह उप-विनियम ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र की समझ या कंपनी या संस्थान या निकाय में स्थायी रूप से शामिल होने के लिए सेवा से सेवानिवृत्ति चाहता है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसमें वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगने के समय प्रतिनियुक्ति पर है।

बशर्ते कि यह उपधारा उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगी जिसे विनियम 2 के खंड (1) के अनुसार सेवानिवृत्त माना जाता है।

2. उप-विनियम (1) के तहत दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता होगी:

बशर्ते कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्ति की अनुमति देने से इनकार नहीं करता है, सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगी।

(3) (ए) उप-नियमन में निर्दिष्ट एक कर्मचारी

(1) नियुक्ति प्राधिकारी को तीन महीने से कम की सेवानिवृत्ति के लिए कारण बताते हुए अनुरोध कर सकता है:

(बी) खंड (ए) के तहत अनुरोध प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, उप-विनियम (2) के प्रावधानों के अधीन, गुण-दोष के आधार पर तीन महीने की नोटिस की अवधि में कटौती के लिए ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकता है और यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि नोटिस की अवधि में कटौती से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी, तो नियुक्ति प्राधिकारी तीन महीने के नोटिस की आवश्यकता में इस शर्तपर छूट दे सकता

है कि कर्मचारी तीन महीने के नोटिस की समाप्ति से पहले अपनी पेंशन के एक हिस्से के कम्युटेशन के लिए आवेदन नहीं करेगा।

(4) एक कर्मचारी, जिसने इस विनियमन के तहत सेवानिवृत्त होने का चुनाव किया है और नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय की आवश्यक सूचना दी है, उसे ऐसे प्राधिकारी की विशिष्ट मंजूरी के बिना अपना नोटिस वापस लेने से रोका जाएगा:

बशर्ते कि ऐसी वापसी का अनुरोध उसकी सेवानिवृत्ति की अपेक्षित तिथि से पहले किया जाएगा।

(5) इस विनियमन के तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की अर्हक सेवा पांच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी, इस शर्त के अधीन कि ऐसे कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई कुल अर्हक सेवा किसी भी मामले में तैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी और यह उसे सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे नहीं ले जाता।

(6) इस विनियम के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की पेंशन इन विनियमों के विनियम (2) के खंड (डी) के तहत परिभाषित औसत परिलब्धियों पर आधारित होगी और उसकी अर्हक सेवा में पांच साल से अधिक की वृद्धि का उसे अधिकार नहीं मिलेगा। उसकी पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए वेतन के किसी भी काल्पनिक निर्धारण के लिए।"

6. उपरोक्त को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि एक कर्मचारी जिसने बीस साल की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, वह बैंक की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का हकदार है, बशर्ते कि वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन महीने का नोटिस दे। उस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि विनियम 29(2) के प्रावधान के संदर्भ में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्ति की अनुमति देने से इनकार नहीं करता है, सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की

समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि विनियम 29(3) (ए) के संदर्भ में नियुक्ति प्राधिकारी उपयुक्त मामलों में तीन महीने के नोटिस की अवधि को इस शर्त के अधीन कम करने में सक्षम है कि कर्मचारी अपनी पेंशन के कम्युटेशन के लिए नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले आवेदन नहीं करेगा।

7. मौजूदा मामले में, मौजी राम-मृतक कर्मचारी ने प्रतिवादी-बैंक में लगभग 34 साल की सेवा प्रदान की थी। इसलिए, वह उस पर लागू विनियमों के अनुसार पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य था। विनियम 29 को पढ़ने से यह भी स्पष्ट है कि मृतक कर्मचारी विनियम 29 के संदर्भ में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का हकदार था क्योंकि उसने 8 अक्टूबर, 2007 तक बीस वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली थी। विनियम 29 (उपरोक्त) के अनुसार मृत कर्मचारी या तो सेवा से इस्तीफा देने या समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने का हकदार था। उस पृष्ठभूमि में सवाल यह है कि क्या 8 अक्टूबर, 2007 का पत्र सरलता से त्यागपत्र का पत्र था या इसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने वाला पत्र भी माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने, जैसा कि पहले देखा गया है, यह विचार किया है कि पत्र इस्तीफे का था जिसके परिणामस्वरूप विनियमों के विनियम 22 के तहत पिछली सेवा को जब्त कर लिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय 8 अक्टूबर, 2007 को कर्मचारी के पत्र में "इस्तीफा" शब्द के उपयोग से प्रभावित हुआ है। हालांकि, "इस्तीफा" अभिव्यक्ति का उपयोग, हमारी राय में, निर्णायक नहीं है। यानी, हमारी राय में, तब भी जब इस न्यायालय ने हमेशा "इस्तीफा" और "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखा है। क्या दिया गया संचार त्यागपत्र का सरल पत्र है या नहीं या इसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध भी माना जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और लागू नियमों के प्रावधानों पर निर्भर करता है। यूको बैंक और अन्य बनाम सांवर मल (2004) 4 एससीसी 412 में इस न्यायालय द्वारा "इस्तीफा" और "स्वैच्छिक

सेवानिवृत्ति" की अभिव्यक्तियों के बीच अंतर पर विस्तृत चर्चा की गई थी। जहां यह न्यायालय एक बैंक कर्मचारी पर लागू यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के प्रावधानों की जांच कर रहा था, जिसने नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रिम सूचना देने के बाद सेवा से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बनाम सीईसीआईएल डेनिस सोलोमन और अन्य (2004) 9 एससीसी 461 में भी ऐसा ही है। यह न्यायालय भारतीय रिज़र्व बैंक पेंशन विनियम, 1990 के प्रावधानों पर विचार कर रहा था, जबकि इसने एक ओर इस्तीफा और दूसरी ओर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बीच अंतर किया। साथ ही निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला ने माना है कि पेंशन न तो कोई इनाम है और न ही अनुग्रह का विषय है बल्कि यह कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवाओं का भुगतान है। डी.एस. नकारा और अन्य बनाम भारत संघ (1983) 1 एससीसी 305 और अध्यक्ष रेलवे बोर्ड और अन्य बनाम सी.आर. रंगधमैय्या और अन्य (1997) 6 एससीसी 623, में इस न्यायालय के निर्णयो में इस विषय पर स्पष्ट घोषणाएं हैं। सुधीर चंद्र सरकार बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और अन्य (1984) 3 एससीसी 369 का भी संदर्भ दिया जा सकता है। जहां इस न्यायालय ने कहा:

> "18. सदियों से अदालतें इस दृष्टिकोण के पक्ष में रहीं कि पेंशन या तो एक इनाम है या नियोक्ता की मधुर इच्छा या कृपा के आधार पर प्रदान की गई वफादार सेवा के लिए एक नि:शुल्क भुगतान है, जो अधिकार के रूप में दावा योग्य नहीं है और इसलिए, पेंशन का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। अदालत के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने क्षेत्र को बरकरार रखा और पेंशन की वसूली के लिए एक मुकदमे को सुनवाई योग्य नहीं माना गया। सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा की आधुनिक धारणाओं के साथ, पेंशन की अवधारणा में आमूल-चूल परिवर्तन आया और यह अब अच्छी

तरह से तय हो गया है कि पेंशन एक अधिकार है और इसका भुगतान नियोक्ता के विवेक पर निर्भर नहीं करता है, न ही नियोक्ता की इच्छा या इच्छानुसार इसे देने से इनकार किया जा सकता है। देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य (1971) 2 एससीसी 330, पंजाब राज्य बनाम इकबाल सिंह (1976) 2 एससीसी 1 और डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ (1983) 1 एससीसी 305। यदि पेंशन जो कि सेवानिवृत्ति लाभ है, सामाजिक सुरक्षा का एक उपाय सिविल मुकदमे के माध्यम से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, हमें ग्रेच्युटी को एक अलग स्तर पर मानने का कोई औचित्य नहीं दिखता है, सेवानिवृत्ति लाभ के मामले में पेंशन और ग्रेच्युटी और इसे पुनर्प्राप्त करने के लिए समान स्तर पर रखा जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

8. इस न्यायालय के कई निर्णयों से यह भी अच्छी तरह से तय हो गया है कि किसी क़ानून की व्याख्या करते समय न्यायालय को विधायी इरादे को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी व्याख्या से बचना चाहिए जो इसके लाभकारी प्रावधानों को प्रतिबंधित, संकीर्ण या पराजित करती हो। एस. अप्पुकुट्टन बनाम थंडलील जानकी अम्मा और अन्य (1988) 2 एससीसी 372 में इस न्यायालय ने देखा:

"16. बहस समाप्त होने के बाद, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने सीए नंबर 165 / 1974 में आदि मैथ्यू बनाम हम्सा हाजी (1987) 3 एससीसी 326, 29.4.1987 को पारित में इस न्यायालय के फैसले की एक प्रति प्रसारित की है, जिसमें केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 द्वारा संशोधित केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 की धारा 7 - डी की व्याख्या केवल उन व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के रूप में की गई है, जिनके निजी जंगलों या असर्वेक्षित भूमि पर कब्जा वैध था। मूल और

अतिचार या जबरन और गैरकानूनी प्रवेश के आधार पर गैरकानूनी कब्जे वाले व्यक्तियों पर नहीं। हमने फैसले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और पाया है कि उसमें दी गई घोषणा किसी भी तरह से उत्तरदाताओं के तर्कों का समर्थन नहीं करती है। केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 की धारा 7-ए, 7-8, 7-सी, 7-डी, 8 और 9 की योजना पूरी तरह से अलग है और इस स्थिति को संदर्भित निर्णय में निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा संक्षेप में सामने लाया गया है। ऊपर। न्यायालय ने अधिनियम की योजना को निम्नलिखित शब्दों में सारांशित किया था: (एससीसी पृष्ठ 330, पैरा 5)

उपरोक्त प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि विधायिका का इरादा केवल उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना था जिनके कब्जे का अर्थ कानूनी रूप से मूल था। उनका या तो यह विश्वास था कि भूमि सरकार की भूमि है, जिस पर वे बाद में अधिकार प्राप्त कर सकते हैं या उन्होंने उन लोगों से पट्टे पर भूमि ली है, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे ऐसे पट्टे देने के लिए सक्षम हैं या उन्होंने इस इरादे से कब्जा कर लिया है। वैध स्वामियों को या वरम इत्यादि जैसी व्यवस्थाओं के आधार पर, जो केवल लाइसेंस की प्रकृति में थे और पट्टे के अधिकार से कम थे। ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा का लाभ देना विधायिका के विचार में नहीं था, जिन्होंने जानबूझकर दूसरों की भूमि पर अतिक्रमण किया था और जिनका कब्जा मूल रूप से गैरकानूनी था। धारा 7-डी में आने वाली अभिव्यक्ति "कब्जे में" का अर्थ "वैध कब्जे में" के रूप में समझा जाना चाहिए।

9. फिर से वतन मल बनाम कैलाश नाथ (1989) 3 एससीसी 79 में, इस न्यायालय ने कहा:

> "9. सभी किरायेदारों को धारा 13-ए का लाभ प्रदान करने की विधायिका की मंशा, बशर्ते कि वास्तविक बेदखली न हुई हो, इसे आगे

उपखंड - सी की शर्तों द्धारा देखा जा सकता है। उप-खंड (सी) के तहत उप-खंड (ए) और (बी) के प्रावधानों को संशोधित अध्यादेश के प्रारंभ होने के बाद पसंदीदा या किए गए संशोधन के लिए सभी अपीलों या आवेदनों पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू किया गया है और इसमें निहित एकमात्र शर्त यह है कि अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले किरायेदार को धारा 13-ए का लाभ देने के लिए अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण के लिए आवेदन की प्रस्तुति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अदालत में आवेदन करना चाहिए... ।"

10. कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम आर.के. स्वामी और अन्य (1994) 1 एससीसी 445 का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जहां इस न्यायालय ने कहा:

"14 - इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त अधिनियम लाभकारी कानून है। यदि, इसलिए, "दुकान" शब्द का अर्थ यह लगाना संभव है कि इसमें एक विज्ञापन एजेंसी की गतिविधि शामिल है, तो उस निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"

11. इसी आशय का भारत संघ और अन्य बनाम प्रदीप कुमारी और अन्य (1995) 2 एससीसी 736 में इस न्यायालय का एक बाद का निर्णय है, जहां इस न्यायालय ने घोषणा की:

"8. हम, शुरुआत में, कह सकते हैं कि पहले उल्लिखित उद्देश्यों और कारणों के विवरण को ध्यान में रखते हुए, धारा 28-ए के अधिनियमन का अंतर्निहित उद्देश्य समान या समान गुणवत्ता के लिए मुआवजे के भुगतान में असमानता को दूर करना है या अधिनियम की धारा 18 के तहत अस्पष्ट और गरीब लोगों के सिविल कोर्ट में

संदर्भ के अधिकार का लाभ नहीं उठा पायेपाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूमि। यह उन सभी पीड़ित पक्षों को एक अवसर प्रदान करके प्राप्त करने की कोशिश की जाती है जिनकी भूमि उसी अधिसूचना के अंतर्गत आती है, उनमें से किसी ने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ न्यायालय से उच्च मुआवजे के भुगतान के लिए आदेश प्राप्त करने के बाद पुनर्निर्धारण की मांग की है। इसलिए, धारा 28-ए एक लाभकारी प्रावधान की प्रकृति में है जिसका उद्देश्य असमानता को दूर करना और अस्पष्ट और गरीब लोगों को राहत देना है जो अधिनियम की धारा 18 के तहत सिविल न्यायालय के संदर्भ के अधिकार का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। लाभकारी कानून के संबंध में, कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि ऐसे कानून के प्रावधानों को लागू करते समय अदालत को एक ऐसे निर्माण को अपनाना चाहिए जो लाभ को बढ़ाने के लिए कानून की नीति को आगे बढ़ाता है, न कि एक ऐसे निर्माण को अपनाता है जिसका इसके द्वारा प्रदत्त लाभ कम करने का प्रभाव पड़ता है। इसलिए, धारा 28-ए के प्रावधानों को उक्त प्रावधान में अंतर्निहित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

12. आइए अब उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में मृत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत पत्र के सही उद्देश्य की जांच करें। रिकॉर्ड से दो अलग पहलू सामने आते हैं। पहला यह है कि मृत कर्मचारी ने बैंक में 34 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की थी और इसलिए, यदि वह समय से पहले छोड़ने का विकल्प चुनता है तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का हकदार था। दूसरा पहलू जो समान रूप से महत्वपूर्ण है, वह यह है कि कर्मचारी ने अपने खिलाफ प्रस्तावित किसी अनुशासनात्मक या अन्य कार्रवाई या स्थानांतरण या पोस्टिंग के किसी आदेश से नाखुश होने या कोई कार्यवाही शुरू होने के कारण नौकरी छोड़ने का विकल्प नहीं चुना था। यदि वह सेवा में बने रहते तो किसी भी नागरिक परिणाम के लिए उनसे मिलने जाते, लेकिन उन बीमारियों के कारण सेवा में बने रहने

में उनकी शारीरिक अक्षमता के कारण, जिनसे वे त्रस्त थे। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि न केवल पत्र में, बल्कि उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में भी कर्मचारी ने समय से पहले सेवा छोडने पर इस पर बहुत जोर दिया है। यदि कर्मचारी वास्तव में उस पद के सही अर्थों में इस्तीफा देने का इरादा रखता है तो ऐसे कोई कारण आवश्यक नहीं थे। वह जिस कारण से पद छोड़ रहा था, वह स्पष्ट रूप से उसके मामले का समर्थन करने के लिए था कि वह परिस्थितियों की मजबूरी के तहत ऐसा कर रहा था। यह क्षेत्रीय प्रबंधक के 23 नवंबर, 2007 के पत्र से स्पष्ट है, जिसमें मृत कर्मचारी की खराब स्वास्थ्य स्थिति को पहचाना गया है और उसके पक्ष में 165 दिनों का बिना वेतन अवकाश स्वीकृत किया गया है। यह 29 नवंबर, 2007 के पत्र से भी स्पष्ट है जिसके द्वारा कर्मचारी के अनुरोध की स्वीकृति के बारे में उसे सूचित किया गया था कि नियोक्ता ने उसके गिरते स्वास्थ्य पर ध्यान दिया था, उसके प्रति प्रबंधन की सहानुभूति व्यक्त की थी और उसकी बीमारी से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। पत्र में कर्मचारी की अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता और संगठन के विकास में उसके द्वारा किए गए योगदान को मान्यता दी गई है। इस हद तक कर्मचारी और नियोक्ता के बीच कोई संवादहीनता नहीं है। हालाँकि, कर्मचारी का मामला यह है कि उसका इरादा सेवा से समयपूर्व/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का था। कर्मचारी के अनुसार, यह बैंक द्वारा अनुरोध स्वीकार किए जाने के तीन सप्ताह के भीतर लिखे गए उनके दिनांक 18 दिसंबर, 2007 के पत्र से भी स्पष्ट है। उक्त पत्र में मृतक-कर्मचारी ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा:

> "इस प्रकार, उक्त अभ्यावेदन के अनुसार मैंने सेवा से अपना इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया है। पूरे कारण और उद्देश्य, जो मैंने अपने उक्त अभ्यावेदन के माध्यम से प्रस्तुत और बताए हैं और मेरी एक वर्ष की शेष सेवा ने मेरी अंतरात्मा को सेवा से स्वैच्छिक

सेवानिवृत्ति लेने के लिये मजबूर कर दिया है न कि शाब्दिक अर्थ में सेवा से इस्तीफा देनेके लिये।"

13. बाद वाले ने एक बार फिर अपने अनुरोध के समर्थन में चिकित्सा प्रमाण पत्र और प्रस्तुतियाँ संलग्न कीं कि पहले लिखा गया पत्र और उसमें प्रयुक्त अभिव्यक्ति को सही भावना से समझा जा सकता है और उसके पक्ष में अंतिम लाभ जारी किया जा सकता है। 8 अक्टूबर, 2007 के पत्र को समयपूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध के रूप में मानने से बैंक प्रबंधन के इनकार की जानकारी कर्मचारी को 24 जून, 2008 को दी गई, जिसमें प्रतिवादी-बैंक ने यूको बैंक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया था जिसके तहत पेंशन विनियमों के विनियमन 22 को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।

14. जब उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में देखा जाता है, तो अपीलकर्ता की ओर से आग्रह की गई इस दलील को खारिज करना मुश्किल है कि मृतक-कर्मचारी ने 8 अक्टूबर, 2007 को लिखे अपने पत्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का इरादा किया था, न कि उसके रोजगार से इस्तीफा देने का। हम कई संबंधित परिस्थितियों के आलोक में ऐसा कहते हैं। सबसे पहले, 8 अक्टूबर, 2007 को पत्र लिखने के समय कर्मचारी की सेवा लगभग डेढ़ वर्ष ही बची थी। किसी के लिए भी यह सुझाव देना बहुत ही अविवेकपूर्ण होगा कि एक बैंक कर्मचारी जिसने इतनी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है कि उसे प्रबंधन की सराहना मिली है, उसने पेंशन आदि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभों को बिना सोचे-समझे छोड़ दिया होगा, जो उसने अपने काम के प्रति उनका निरंतर समर्पण से अर्जित किए थे। यदि पेंशन एक इनाम नहीं है, बल्कि एक अधिकार है जो कर्मचारी को उसके द्वारा किए गए कई वर्षों के ईमानदार और अच्छे काम के कारण प्राप्त होता है, तो न्यायालय यह मानने में धीमा होगा कि कर्मचारी बिना किसी ठोस सबूत के ऐसे मूल्यवान अधिकार को माफ करने या त्यागने का इरादा रखता है। किसी

भी दर पर यह सुझाव देने के लिए कुछ बाध्यकारी परिस्थिति होनी चाहिए कि कर्मचारी ने जानबूझकर उस अधिकार और लाभ को छोड़ दिया है, जिसे उसने इतनी मेहनत से हासिल किया था। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री ऐसे किसी भी सचेत समर्पण परित्याग या पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभ के अधिकार की छूट का सुझाव देती है, हम पाते हैं कि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री स्पष्ट रूप से सुझाव देती है कि कर्मचारी के पास उस लाभ के अलावा आय या जीविका का कोई स्रोत नहीं था जो उसने लंबे वर्षों की सेवा के लिए अर्जित किया था। दिनांक 8.10.2007 के पत्र को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है, जिसमें कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति लाभों को जल्द से जल्द जारी करने की मांग करता है ताकि वह आवश्यक चिकित्सा उपचार से गुजर सके। पत्र, जैसा कि पहले देखा गया है, इस तथ्य पर जोर देता है कि अपने भरण-पोषण के लिए कर्मचारी पूरी तरह से ऐसे लाभों पर निर्भर है। इस दृष्टि से हमारे लिए यह कहना मुश्किल है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभों के संदर्भ में जो उसका अधिकार था उसे छोड़ने का इरादा है, जब ऐसे लाभ न केवल उसके जीवित रहने के लिए बल्कि उसके चिकित्सा उपचार के लिए भी एकमात्र स्रोत थे, जिसकी उसे तत्काल आवश्यकता थी। किसी कर्मचारी द्वारा अर्जित कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार की छूट के लिए, यह आवश्यक है कि वह स्पष्ट और स्पष्ट, सचेत और परिणामों की पूरी जानकारी के साथ हो। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से ऐसा कोई इरादा नहीं लगाया जा सकता है। कर्मचारी के बाद के पत्र और संचार, जिन्हें रिकॉर्ड पर रखा गया है, को बाद में किया गया विचार नहीं कहा जा सकता है। 8 अक्टूबर, 2007 के पत्र को समय की दृष्टि से निकट होना कर्मचारी के इरादों को स्पष्ट करने वाले बाद के संचार का एक हिस्सा माना जाना चाहिए, कम से कम कर्मचारी के कृत्य के अंतर्निहित वास्तविक इरादे को निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए।

15. हमारी राय में, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पेंशन योजना या पेंशन विनियमों के लाभकारी प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या की गई है ताकि ऐसे प्रावधानों के तहत लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों से इनकार करने के बजाय उसी उद्देश्य को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे मामलों में जहां किसी कर्मचारी के पास पेंशन देने के लिए अर्हक सेवा के अपेक्षित वर्ष हैं, और जहां वह लागू सेवा शर्तों के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग कर सकता है, कथित इस्तीफे को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध मानकर पेंशन का लाभ देने की अनुमति दी गई है। हमें वर्तमान मामले में भी ऐसा करने के लिये कोई बाध्यकारी कारण नजर नहीं आते, जो हमारी राय में मूल रूप से मृत कर्मचारी द्वारा इस्तीफा देने के बजाय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने का मामला है।

16. इस स्तर पर हम इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं जिनमें कुछ इसी तरह के प्रश्नों की जांच की गई है और इस न्यायालय द्वारा उत्तर दिए गए हैं। सुधीर चंद्र सरकार बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और अन्य (1984) 3 एससीसी 369 में, कंपनी के एक स्थायी गैर अनुबंधित कर्मचारी ने 29 वर्षों तक सेवा की थी जिसके बाद उसने अपना इस्तीफा दे दिया जिसे नियोक्ता ने बिना शर्त स्वीकार कर लिया। कंपनी के सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी नियमों में सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रावधान नहीं था। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को पलटते हुए कहा कि इस्तीफे द्वारा सेवा समाप्त करना, इस्तीफे द्वारा सेवानिवृत्ति के समान है, जिससे कर्मचारी सेवानिवृत्त लाभों का हकदार हो जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित अनुच्छेद उपयुक्त है:

> "7. प्रतिवादी का तर्क यह है कि वादी सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने पद से इस्तीफा देकर कंपनी की सेवा छोड़ दी। इस पहलू ने कुछ हद तक उच्च न्यायालय के दिमाग को उत्तेजित किया। इसे पहले निपटाया जा सकता है। यह न केवल विवाद में है, बल्कि

वास्तव में स्वीकार किया गया है कि वादी ने 31 दिसंबर, 1929 से 31 अगस्त, 1959 तक निरंतर सेवा प्रदान की। सटीक गणना पर, वादी ने 29 साल और 8 महीने तक सेवा प्रदान की। नियम 6 (ए) जो ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करता है, यह प्रावधान करता है कि कंपनी का प्रत्येक स्थायी गैर-अनुबंधित कर्मचारी, चाहे उसे मासिक, साप्ताहिक या दैनिक आधार पर भुगतान किया जाता हो, सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होगा, जो लगातार पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए आधे महीने के वेतन या मजदूरी के बराबर होगा। सेवा अधिकतम 20 वर्षों के वेतन या मजदूरी के अधीन है, बशर्ते कि जब कोई कर्मचारी 15 वर्षों की निरंतर अवधि के लिए कंपनी की सेवा करने से पहले नियम 11(2)(i) और (iii) के तहत मर जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है या छुट्टी दे दी जाती है, उसे उसमें उल्लिखित दर पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। नियम 1(जी) में "सेवानिवृत्ति" शब्द को "कदाचार के कारण सेवामुक्त करके हटाने के अलावा किसी अन्य कारण से सेवा की समाप्ति" के रूप में परिभाषित किया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि वादी मासिक आधार पर भुगतान पाने वाली कंपनी का एक स्थायी गैर-अनुबंधित कर्मचारी था और उसने 29 वर्षों से अधिक समय तक सेवा प्रदान की और उसकी सेवा समाप्त हो गई। उनके त्यागपत्र देने का कारण जो बिना शर्त स्वीकार कर लिया गया था। यह सुझाव नहीं दिया गया है कि उन्हें कदाचार के कारण सेवामुक्त कर दिया गया था। निस्संदेह, इसलिए, वादी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया क्योंकि पत्र अनुबंध 'बी' दिनांक 26 अगस्त, 1959 द्वारा, प्रस्तुत किया गया त्यागपत्र वादी

द्वारा उनके पत्र दिनांक 27 जुलाई 1959 के अनुसार स्वीकार कर लिया गया था और उन्हें 1 सितंबर 1959 से उनकी सेवा से मुक्त कर दिया गया था। सेवा की समाप्ति इस प्रकार वादी के इस्तीफे को प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण हुई थी। वादी अभिव्यक्ति के अर्थ के अंतर्गत, इस प्रकार प्रतिवादी की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है और वह नियम 6 के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए योग्य है।"

17. भारत संघ और अन्य बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल पी.एस. भार्गव (1997) 2 एससीसी 28 में, यह अदालत एक ऐसे मामले से निपट रही थी जहां प्रतिवादी को इस आधार पर पेंशन से वंचित कर दिया गया था कि वह स्वेच्छा से सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था। भारत संघ द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी पर लागू पेंशन विनियमों का विनियमन 16 स्वैच्छिक इस्तीफे से संबंधित नहीं है और इसलिए, प्रतिवादी को पेंशन से इनकार करने के लिए सेवा में दबाव नहीं डाला जा सकता है। इस न्यायालय ने कहा:

"19. विनियम 16 स्वैच्छिक इस्तीफे के मामले को कवर नहीं करता है। विनियम 16 (बी) उस मामले को संदर्भित करता है जहां एक अधिकारी जिसके पास अर्हक सेवा की न्यूनतम अवधि है, उसे इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है, जिसकी पेंशन कम की जा सकती है। क्या इस विनियमन का उद्देश्य किसी व्यक्ति से उसके स्वैच्छिक इस्तीफा देने पर अंतिम लाभ का अधिकार छीनना था, तो विनियम 16 (बी) के समान एक विशिष्ट प्रावधान विनियमों में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। एक बार जब किसी अधिकारी के खाते में अर्हक सेवा की न्यूनतम अवधि आ जाती है, तो वह पेंशन पाने का अधिकार अर्जित कर लेता है और जैसा कि विनियमों का मानना है, वह अधिकार तभी छीना जा सकता है जब विनियम 3 या 16

के तहत कोई आदेश पारित किया जाता है। स्वैच्छिक इस्तीफे के मामले वे अधिकारी, जिनके पास अर्हक सेवा की न्यूनतम अवधि है, इन दो विनियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं और इसलिए, ऐसे अधिकारी, जो स्वेच्छा से इस्तीफा देते हैं, उन्हें स्वचालित रूप से टर्मिनल लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है।

18. शील कुमार जैन बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (2011) 12 एससीसी 197 में, तथ्य कुछ हद तक मौजूदा मामले के समान थे। उस मामले में अपीलकर्ता एक पेंशन योजना द्वारा शासित एक बीमा कंपनी का कर्मचारी था, जिसमें मौजूदा मामले की तरह, किसी कर्मचारी द्वारा अपने रोजगार से इस्तीफा देने पर उसकी पूरी सेवा जब्त करने का प्रावधान था। अपीलकर्ता ने त्याग पत्र प्रस्तुत किया जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त योजना के तहत उसके सेवा लाभों से इनकार कर दिया गया। हालाँकि, इस न्यायालय ने माना कि चूंकि कर्मचारी ने अर्हक सेवा पूरी कर ली थी और वह इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का हकदार था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसने इस्तीफा दे दिया है ताकि उसकी पेंशन खत्म हो जाए। इस न्यायालय ने कहा:

"25. 1995 पेंशन योजना के पैरा 22 में कहा गया है कि निगम या कंपनी की सेवा से किसी कर्मचारी के इस्तीफे से उसकी पूरी पिछली सेवा जब्त हो जाएगी और परिणामस्वरूप वह पेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन यह शब्द "इस्तीफा" को परिभाषित नहीं करता है। 1995 के पैरा 30 के उप-पैरा (1) के तहत पेंशन योजना, एक कर्मचारी, जिसने 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में 90 दिनों से कम का नोटिस देकर और 1995 पेंशन योजना के पैरा 30 के उप-पैरा (2) के तहत सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता होगी। चूंकि "इस्तीफा" के विपरीत "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" में पिछली सेवाओं को जब्त नहीं किया

जाता है और इसके बजाय पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त की जाती है, जिस कर्मचारी पर 1995 पेंशन योजना का पैरा 30 लागू होता है, उसे सेवा से "इस्तीफा" नहीं दिया जा सकता है।

26. वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता ने 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली थी और नियुक्ति प्राधिकारी को सेवा छोड़ने के अपने इरादे के बारे में लिखित रूप में 90 दिनों से कम का नोटिस नहीं दिया था और नियुक्ति प्राधिकारी ने अपीलकर्ता का नोटिस स्वीकार कर लिया और उसे सेवा से मुक्त कर दिया। इसलिए, 1995 पेंशन योजना का पैरा 30 अपीलकर्ता पर लागू होता है, भले ही प्रतिवादी '1 कंपनी के महाप्रबंधक को दिनांक 16-9-1991 को लिखे अपने पत्र में उन्होंने "इस्तीफा" शब्द का इस्तेमाल किया था।

19. परिणामस्वरूप यह अपील सफल होती है और इसके द्वारा अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है और मृत कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका को प्रतिवादी-बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह 8 अक्टूबर, 2007 के पत्र को कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक नोटिस के रूप में माने और तीन महीने की नोटिस अवधि के लिए कटौती के लिए। इस दृष्टिकोण के आधार पर सक्षम प्राधिकारी नोटिस अवधि में कटौती और/या मृत-कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों में से तीन महीने के वेतन की कटौती के सवाल पर विचार कर सकता है, मृतक-कर्मचारी के तहत देय सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान का दावा पेंशन सहित संबंधित नियमों पर कार्रवाई की जाएगी और अपीलकर्ता-विधवा के पक्ष में यथाशीघ्र जारी किया जाएगा, लेकिन इस आदेश की एक प्रति बैंक को दिए जाने की तारीख से छह महीने के भीतर नहीं। ऊपर बताए अनुसार छह महीने के भीतर निर्देशों का पालन करने में बैंक के विफल होने की स्थिति में, कर्मचारी और उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा को देय राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। जिस

तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त हो रही है। पक्षकारो को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अपील स्वीकार की गई।

कल्पना के.त्रिपाठी

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।